कौन हैं नौजवानों के रोल माडल ?

प्रभात कुमार रॉय

साफ्टवेयर सैक्टर के दिग्गज नायक एन.आर. नारायणमूर्ति ने अत्यंत संजीदा अंदाज में फरमाया कि यह बेहद अफसोसनाक तथ्य है कि भारतीय नौजवानों के रोल माडल बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग बन रहे हैं। नारायणमूर्ति का कहना है कि जो भ्रष्टाचारी और बेईमान हैं और जिनकी जिंदगी सब कुछ चलता-चलाता है के फारमूले पर टिकी हैं , वस्तुतः ऐसे लोग ही भारतीय समाज में दौलतमंद और ताकतवर हो उठे हैं। इसी कारणवश नौजवानों को मध्य गलत पैगाम चला गया कि कामयाबी हासिल करने के लिए बेईमानी और भ्रष्टाचार का रास्ता अधिक कारगर सिद्ध हो सकता है।

एन.आर.नारायणमूर्ति के दर्दभरे उदगार में बहुत दमखम है। आजादी के संपूर्ण दौर में प्रारम्भ से ही जबकि जंग ए आजादी के आदर्शवादी, बलिदानी और तपस्वी योद्धागण जीवित थे, भारतीय सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार ने अपनी दस्तक दी। जंग ए आजादी के दौर के नेशनल हीरो रहे प्रधानमंत्री पं0 जवाहरलाल नेहरु के शासन काल में 1948 में जीप स्कैंडल प्रकाश में आया। पं0 नेहरु के अत्यंत निकटवर्ती रहे कृष्णा मेनन और जनरल थिमैया का नाम इस स्कैंडल में गूंजा। भारतीय फौज़ के लिए जीपों की खरीदारी में भारी घपला हुआ। उस वक्त कृष्णा मेनन और जनरल थिमैया को उनके पदों से हटा दिया गया, किंतु बाद में पं0 नेहरु ने कृष्णा मेनन को रक्षामंत्री को तौर पर बहाल कर दिया। 1951 को मूंदडा कॉंड उजागर हुआ जिसकी तहकीकात ए.डी. गोरेवाला ने अंजाम दी। मूंदडा कॉंड में केबिनेट मिनिस्टर रफीअहमद किदवई को हटाने की सिफारिश की गई। इस सिफारिश को पं0 नेहरु ने दरकिनार कर दिया। पं0 नेहरु के शासन काल में केबिनेट मिनिस्टर टी.टी कृष्णमाचारी और के.डी. मालवीय चर्चित शासकीय स्कैंड्लस में फँसे, किंतु इनका कुछ नहीं बिगड़ा। 1960 के दशक में पंजाब में प्रताप सिंह कैरों जैसे भ्रष्ट, बेईमान और अपराधी वृति के मुख्यमंत्री को प्रश्रय प्रदान करके पं0 नेहरु ने एक गलत नज़ीर पेश की। कुख्यात नागरवाला कॉंड ने इंदिरा गाँधी को कंलकित किया। बॉफोर्स तोप स्कैंडल में शक की सुई ने राजीव गाँधी को सत्ताच्चुत किया। भ्रष्टाचार की गंदगी सदैव ही शीर्ष सत्ता से नीचे की ओर प्रवाहित हुई। वस्तुतः राष्ट्र के नौजवानों को सत्ता के शीर्ष पर विराजमान रहे नेताओं की ओर से यही पैगाम मिलता रहा कि यदि सत्तानशीन होना चाहते हो तो देश से अधिक दौलत से प्यार करो और फिर यह दौलत चाहे किसी अवैध तरीके से हासिल की क्यों न की गई हो।

शासन और राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण की रोकथाम करने के लिए 1960 में पं0 नेहरु ने संथानम कमेटी नियुक्त की। संथानम कमेटी की सिफरिशों को कदाचित लागू नहीं किया गया। 1995 में

फिर से राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के निराकरण के लिए एन.एन, वोहरा कमेटी का गठन किया गया। एन.एन वोहरा कमेटी की सिफारिशों का भी वही हश्र हुआ जैसा कि संथानम कमेटी की सिफारिशों का हुआ। भ्रष्टाचार और बेईमानी का मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की गई। शासकीय भ्रष्टाचार में दिनों दिन इज़ाफा होता चला गया। ईमानदार छवि वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने तो शासकीय भ्रष्टाचार के पुराने तमाम रिकार्ड्स को ध्वस्त करते हुए नए विश्व रिकार्ड बना दिए। राजनेताओं के साथ कदम से कदम मिलाते हुए उच्च पदों पर विराजमान नौकरशाहों ने भी भ्रष्टाचार के नए रिकार्ड कायम किए। यूपी के पूर्व केबिनेट सैक्रेटरी अखंडप्रताप सिंह से एक हजार करोड़ की अवैध संपदा बरामद की गई। कौफीन काँड के तहत तत्कालीन डिफैंस सेक्रेटरी पर मुकदमा दायर किया गया। अभी हाल ही में आंध्रा के केबिनेट सैक्रेटरी आचार्य को भ्रष्टाचार के संगीन इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया।

संगीन अपराधियों ने भी शनैः शनैः अपना स्थान सक्रिय राजनीति में सुनिश्चित किया। वर्तमान लोकसभा में तकरीबन एक चौथाई सदस्य आपराधिक पृष्ठभूमि के मौजूद हैं। संगीन अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक आयद करने की एन.एन वोहरा कमेटी की सिफारिशों की विगत 17 वर्षो से केंद्र में सत्तानशीन रही प्रत्येक राष्ट्रीय दल की सरकार ने घोर उपेक्षा की। सफेदपोश और संगीन अपराधियों पर कड़ी लगाम कसनें में अदालतें भी नाक़ाम ही सिद्ध हुई। शीर्ष नेताओं और बड़े नौकरशाहों पर दायर किए गए आपराधिक मामलात दशकों तक न्यायालयों में लंबित पड़े रहे। पूर्व टैलिकॉम मिनिस्टर सुखराम को दो दशक के बाद सजा तो दी गई, किंतु इसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। सफेदपोश और संगीन अपराधियों को पल्लवित और सत्तानशीन होते हुए देखकर राष्ट्र के नौजवानों को मध्य केवल यही संदेश जाता रहा कि शार्टकट क्रिमिनल्स और करप्ट्स ही जिंदगी में कामयाबी को जल्द हासिल कर सकते हैं और देश का कानून भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। सफेदपोश और संगीन अपराधियों ने विदेशी बैंकों में लाखों करोड़ की अकूत काली दौलत के अंबार लगा दिए, किंतु सरकार का जालिम कहर टूटा तो काली दौलत को वापस स्वदेश लाकर इसका राष्ट्रीयकरण करने की मांग करने वाले स्वामी रामदेव के हजारों अनुयायियों पर। राष्ट्र को लूटकर काली दौलत जमा करने वालो का हुकूमत अभी तक तो कुछ नहीं बिगाड़ सकी।

आपराधिक भ्रष्टाचार लगाम कसने के लिए सशक्त लोकपाल बिल पारित करने संसदीय संकल्प के साथ मनमोहना हुकूमत ने जैसा बर्बर सलूक किया है वह तो एक गाथा बन चुका है। राष्ट्र की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के सपने कदाचित साकार नहीं हुए। राष्ट्र की आधी से अधिक आबादी गुरबत और जहालत के नर्क में दम तोड़ती रही। राष्ट्र के मेहनतकश किसान- मजदूरों की पसीने की गाड़ी कमाई को लूट कर मुट्ठीभर हाकिम खानदान अपने खजाने भरते रहे। 12 करोड़ से

अधिक नौजवान निर्मम बेरोजगारी के शिकार बने रहे। ऐसे दुर्धष हालात में यदि लाखों की तादाद में भारतीय नौजवान नक्सलवाद, आतंकवाद और संगीन अपराधों की और आकृष्ट हो उठे तो बहुत विस्मय नहीं होना चाहिए। नक्सलवाद कई दशक से भारतीय नौजवानों का आकर्षण बिंदु बना रहा। विस्तारित होकर 20 राज्यों में नक्सलवाद अपनी घुसपैठ कायम कर चुका है। 1950 के दशक से आतंकवाद का आग़ाज नागालैंड से हुआ और मिजोरम, पंजाब, असम, मणिपुर, कश्मीर आदि प्रातों में लाखों जाने ले चुका है। नौजवानों में संगीन अपराधों का ग्राफ जिस द्रुत गति से बढता रहा, वह भले ही राष्ट्रीय चिंता का विषय नहीं रहा किंतु इसके चलते प्रत्येक नागरिक स्वयं को असुरक्षित महसूस करता रहा।

एन.आर. नारायणमूर्ति की बात पर राष्ट्र के शासक वर्ग को तव्वजो देनी चाहिए, जिसकी कारगुजारियों का सबसे अधिक प्रभाव राष्ट्र के नौजवानों पर कायम होता है। देश का वरिष्ठ शासक वर्ग सर्वप्रथम स्वयं को आदर्श के तौर पर पेश करे, तभी नौजवानों से उम्मीद की जा सकती है कि वे भी मेहनत, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा का आदर्श मार्ग अख़त्यार करगें।